देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 30.05.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
- नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया, उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी।
- चमोली की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' का आयोजन होगा, सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश–विदेश के धावक हिस्सा लेंगे।
- हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों तेज; जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रांतीयकरण नीति

प्रदेश में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक माह के भीतर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि नई नियमावली लागू होने के बाद उन अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिनकी प्रबंधन समितियां शासन को राजकीयकरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को लेकर कुछ मामलों के न्यायालय में लंबित होने के कारण वरिष्ठता और अन्य लाभों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। ऐसे में पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्ययभार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

संबोधन

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–खरीफ अभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित

इस दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों, अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसल की तैयारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2026 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा बीज, खाद और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान लघु और सीमान्त श्रेणी के हैं, इसलिए सरकार क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की खपत कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि परम्परागत कृषि विकास योजना और नमामि गंगे योजना के माध्यम से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत है। वहीं, जैविक उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर 337 जैविक आउटलेट स्थापित किए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श से किसानों की उन्नति और कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

ब्रिक्स अकादमिक मिड–टर्म सम्मेलन

देहरादून के दून विश्वविद्यालय में कल अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड–टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथियोपिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान समकालीन वैश्विक चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार–विमर्श किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रो. हर्ष वी. पंत तथा विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं ब्रिक्स उप–शेरपा शंभू एल. हक्की ने किया।

सम्मेलन की थीम "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण" पर केंद्रित रही, जो वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम है। सम्मेलन में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए तथा सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

शिविर आयोजन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और एसबीआई आरसेटी में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन–देन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

शिविर में प्रतिभागियों को केवाईसी की अनिवार्यता, री–केवाईसी प्रक्रिया, केंद्रीय केवाईसी और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल लेन–देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा फर्जी कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंक के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए।

पोर्टल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड–सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार पहली जून से शुरू हो जायेगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन

चमोली जिले की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा।

आयोजन में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सेना द्वारा आवास, चिकित्सा सहायता और मार्ग सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं में सहयोग दिया जा रहा है, जिससे प्रतियोगिता का सुरक्षित और सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस आयोजन से स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके चलते होम–स्टे, परिवहन, भोजन और गाइड सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल आयोजन

की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और प्रतिभागियों के साथ–साथ स्थानीय समुदायों में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

बैठक

आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ज़िलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सड़कों की मरम्मत और सड़क सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ मेले से पहले सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने पर जोर दिया।

सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन आने वाली सभी सड़कों पर पेचवर्क और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण न होने देने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

हिंदी पत्रकारिता दिवस

आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र ''उदन्त मार्तण्ड'' का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर है।

हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जनजागरूकता बढ़ाने तथा जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है।

वहीं, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफल पत्रकारिता की पहचान है और यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम भी है।

प्रगति

छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95 दशमलव नौ प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत से बढ़कर 76 दशमलव दो प्रतिशत हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96 प्रतिशत से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं।